जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 72 प्रभात चूरू, बुधवार 9 जुलाई, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता का निधन

मुख्यमंत्री व भाजपा के अनेक नेता अंतिम यात्रा में शरीक हुए

जोधपुर, 8 जुलाई (कासं)। केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का मंगलवार सुबह जोधपुर में निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। हाल ही में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जोधपुर एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एम्स के मुताबिक, मंगलवार सुबह 11 बजकर 52 मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली। जोधपुर में मंगलवार शाम उनका अंतिम संस्कार किया गया।

- मूलतः पाली जिले के जीवंद कला के निवासी दाऊलाल वैष्णव बाद में जोधपुर आकर बस गये थे। वे अपने गाँव में सरपंच रहे थे तथा सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को जोधपुर में केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता स्व. दाऊलाल वैष्णव की अंत्येष्टि में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को जोधपुर में केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता स्व. दाऊलाल वैष्णव की अंत्येष्टि में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने जोधपुर मोक्षधाम में स्व. दाऊलाल वैष्णव की पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए और पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने और इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की।

दाऊलाल वैष्णव मूलतः पाली जिले के जीवंद कला- निवासी थे। बाद में परिवार के साथ जोधपुर में आकर बस गए थे। रातानाड़ा भास्कर चौराहा के पास महावीर कॉलोनी में उनका घर है। वे अपने गांव में सरपंच भी रह चुके थे और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। दाऊलाल वैष्णव ने जोधपुर में एक वकील और कर सलाहकार के रूप में लंबे समय तक कार्य किया।

उनके परिवार में पत्नी सरस्वती वैष्णव, बड़े बेटे अश्विनी वैष्णव और छोटे बेटे आनंद वैष्णव हैं।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव की उनके घर से बैकुंठी निकाली गई।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अश्वनी पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बने

चंडीगढ़ , 8 जुलाई। पंजाब में भाजपा ने बड़ा बदलाव करते हुए पठानकोट से विधायक अश्वनी कुमार शर्मा को पंजाब भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है तथा सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले अश्वनी कुमार शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

अश्वनी कुमार शर्मा कॉलेज के दिनों से ही आरएसएस और भाजपा की छात्र शाखा एबीवीपी से जुड़े हुए थे। वह 2007 से 2010 तक पंजाब भाजपा के महासचिव तथा गुरदासपुर जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। सन् 2004 में वे पार्टी की युवा शाखा के प्रधान भी रहे।

- पंजाब, भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ इस्तीफा दे चुके हैं, हालांकि, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, पर, वे पार्टी में सक्रिय नहीं हैं।

गौरतलब है कि पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी हाईकमान ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। इससे पहले पंजाब में चार विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान भी सुनील जाखड़ सक्रिय नहीं दिखे थे। उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व से पद की जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध किया था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चिराग पासवान क्या वाकई में बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे?

क्या उनकी यह घोषणा केवल एनडीए गठबंधन में ज्यादा सीटें लेने के लिए सिर्फ एक सुनियोजित तरीका है?

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 जुलाई। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सीट बंटवारे को लेकर अपनी सौदेबाज़ी की स्थिति को मजबूत करते हुए, एलजेपी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वे खुद राज्य विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर मेहनत करने का आग्रह किया है।

- अधिकतर यह ही माना जा रहा है कि अपनी सीटों का कोटा बढ़वा कर चिराग फिर चुपचाप बैठ जायेंगे।
- पर, जिस तीव्रता से वे मु.मंत्री नीतीश कुमार पर आक्रमण कर रहे हैं, यह भी हो सकता है कि पिछली बार की भांति वे एक बार फिर नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए उनकी पार्टी के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे।
- पिछली बार उनकी इस नीति के कारण, नीतीश कुमार को काफी नुकसान हुआ था और नीतीश की पार्टी तीसरे नम्बर पर आई थी, भाजपा व आरजेडी के बाद।

जहाँ चिराग के पिता और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान मुख्य रूप से केन्द्रीय राजनीति में सक्रिय रहे, वहीं हाल के महीनों में चिराग के संदेशों से यह संकेत मिल रहा है कि वे बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। यह संकेत देकर कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, चिराग जाहिर तौर पर एनडीए के सीट बंटवारे में बड़ा हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं।

2020 के चुनावों में चिराग ने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से कई जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ थे। हालाँकि चिराग की पार्टी केवल मटिहानी सीट जीत ही सकी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी का जेडीयू पर नुकसानदायक प्रभाव पड़ा तथा भाजपा और आरजेडी के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन पाई।

उस समय भाजपा पर यह आरोप लगा था कि उसने नीतीश कुमार की जेडीयू के खिलाफ चिराग का उपयोग किया था, और इस बार भी वैसी ही रणनीति सामने आती दिख रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि चिराग ने रविवार को सारण में एक सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला और गिरती कानून व्यवस्था के हालात को उजागर किया, जिसका उदाहरण हाल ही में पटना के व्यवसायी गोपाल ख़ेमका की दिनदहाड़े हत्या है। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराई हुई है। राज्य में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इज़रायल के प्र.मंत्री नेतन्याहू ने भी ट्रंप को नोबल पुरुस्कार के लिए मनोनीत किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 जुलाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को सोमवार को नोबैल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। यह नामांकन इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप ने "एक के बाद एक क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कोशिश की है।"

- पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर तो पहले ही ट्रंप का नाम चला चुके हैं, नोबल शांति पुरुस्कार के लिये।
- इज़रायल के प्र.मंत्री ने वाइट हाउस में भोज के दौरान ही राष्ट्रपति ट्रंप को उस खत की प्रतिलिपि भी दी जो उन्होंने नोबल शांति पुरुस्कार कमेटी को लिखा है।
- ट्रंप को नोबल शांति पुरुस्कार कमेटी से शिकायत है, कमेटी ने उनके साथ अभी तक न्याय नहीं किया है। क्योंकि, उन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत-पाकिस्तान में युद्ध विराम करवाया, मिस्र व इथियोपिया में समझौता करवाया तथा इज़रायल व अरब देशों के बीच संबंध सामान्य करवाये, और अब शीघ्र ही यूक्रेन व गाज़ा में भी शांति स्थापित करा देंगे।

वाइट हाउस में आयोजित एक रात्रिभोज के दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप को वह पत्र सौंपा, जो उन्होंने नोबैल शांति पुरस्कार समिति को भेजा था। हालांकि, ट्रंप को नामांकित करने वाले नेतन्याहू पहले व्यक्ति नहीं हैं। उनसे पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, जो पाकिस्तान के 11वें सेनाध्यक्ष हैं, ने उन्हें इस पुरस्कार के लिए नामित किया था।

डॉनल्ड ट्रंप को पहले भी कई बार उनके समर्थकों और कुछ सांसदों द्वारा नोबैल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा चुका है। ट्रंप ने नॉर्वे की नोबैल कमेटी की यह कहकर आलोचना की है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई भर्ती पेपर लीक में सुनवाई बुधवार को जारी रहेगी

जयपुर, 8 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सोमवार को दिए आदेश में, महाधिवक्ता की आपत्ति के बाद, संशोधन किया है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में राज्य सरकार को संबंधित रिकॉर्ड साथ लाने के निर्देश देते हुए प्रकरण की सुनवाई बुधवार को तय की है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने ये आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- महाधिवक्ता की प्रार्थना पर हाई कोर्ट ने सोमवार के आदेश को संशोधित किया।

आज महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि अदालत ने सोमवार के आदेश में यह कहा है कि महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के वकीलों की इस दलील का खंडन नहीं किया कि पेपरलीक में कई कोचिंग सेंटर, अधिकारी व आरसीएससी के सदस्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या 160 वर्षों से चला आ रहा दो पार्टी सिस्टम अब टूटेगा अमेरिका में?

63 प्रतिशत अमेरिकावासियों की सोच है कि अब अमेरिका को एक और राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 जुलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के समाप्त होने और डॉनल्ड ट्रंप के सत्ता में मज़बूती से आने के बाद, अमेरिका की जनता के सामने एक गहरा सवाल खड़ा है-जो यह तय करने से भी अधिक गंभीर है कि व्हाइट हाउस में कौन है, क्या अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था स्वयं ही टूट रही है? अभूतपूर्व ध्रुवीकरण से लेकर बाहरी राजनीतिक आंदोलनों के उभार तक, अमेरिकी लोकतंत्र की नींव पहले कभी इतनी गहराई से सवालों के घेरे में नहीं आई।

- अब अमेरिका में जनता का इस बात से विश्वास उठ रहा है कि कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति सही निर्णय देंगे, चाहे चुनाव हो या कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया।
- यह धारणा घर कर गई है कि सिस्टम अब साधारण आदमी के लिए काम नहीं करता।
- तो क्या अब अमेरिका धीरे-धीरे "सॉफ्ट तानाशाही" की ओर अग्रसर हो रहा है?

दशकों तक अमेरिका ने खुद को संवैधानिक लोकतंत्र का वैश्विक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, जिसकी जड़ें "चैक एंड बैलेंस" प्रणाली, संस्थागत अखंडता और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण में थीं। लेकिन आज, यही स्तंभ दरकते नज़र आ रहे हैं। एक के बाद एक सर्वे यह दिखा रहे हैं कि संसद (कांग्रेस), सुप्रीम कोर्ट और यहां तक कि राष्ट्रपति पद में भी जनता का भरोसा तेज़ी से गिर रहा है। चुनावों और न्याय की निष्पक्षता को लेकर शासन तंत्र की सक्षमता पर भरोसा ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुँच चुका है।

इस वर्तमान संकट की जड़ में यह बढ़ती धारणा ही है कि यह व्यवस्था अब आम अमेरिकियों के लिए काम नहीं कर रही। दो प्रमुख पार्टियों के वर्चस्व ने शासन से ज़्यादा गतिरोध पैदा किया है। कभी अमेरिकी लोकतंत्र की पहचान रही "विधाई समझौता व्यवस्था" अब लगभग समाप्त हो चुकी है। इसके बजाय, कार्यपालिका के आदेशों और न्यायिक फैसलों के ज़रिए पक्षपातपूर्ण एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह सिर्फ एक "अकार्यशीलता" नहीं, बल्कि संस्थापक सिद्धांतों के खिलाफ एक विकृति है।

इसी बीच, सार्वजनिक संवाद में "सच्चाई" की अवधारणा भी संकट में है। गलत जानकारी (डिसइन्फॉर्मेशन) बिना रोकटोक फैल रही है। राजनेता चुनाव नतीजों की वैधता को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। 2020 में, अमेरिकी इतिहास में पहली बार, एक सत्तासीन राष्ट्रपति ने अपनी हार स्वीकार करने से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)